funds, there is no reservation on our side in providing that facility, provided the State Government gives free accommodation.

Shortage in fertilizers supply

*367. SHRIMATI JAYA BACHCHAN:††

SHRI AMAR SINGH:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there had been an upsurge in the sale of MOP fertilizers during the current kharif season, which resulted in the short fall in the supply of fertilizers to the farmers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps Government have taken to meet the shortage and the result thereof?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN). (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There is an increase of about 57% in the sale of MOP to farmers upto 31.7.2004 during current Kharif 2004. 5.53 lakh MT MOP has been sold upto 31.7.2004 as compared with the sale of 3.51 lakh MT in the corresponding period last year. Some of the State Governments have reported inadequate supplies of MOP.

(b) and (c) There was an unprecedented increase in the price of MOP in the international market, this year, because of which there was delay in finalisation of MOP price. The Government has now decided to consider this hike in international prices for announcement of concession/ subsidy and imports are now taking place in adequate quantities.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I am partly satisfied with the answer. But I have a supplementary. Part (a) of my supplementary is whether the Government proposes to revive the closed fertilizer units. Most of them are located in the eastern part of the country where the consumption of fertilizer is below the national average. If it is so, what are the details? Part (b) of my supplementary is whether the Government proposes to review the present system of fertilizer subsidy which is being

††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Jaya Bachchan.

given to producers instead of the farmers as per the practice in the developed countries.

श्री राम विलास पासवानः सभापति जी , ये प्रश्न एम0ओ0पी के संबंध मे, पोटाश के संबंध में है, जया जी ने प्रश्न पूछे है। जहां, तक उनके पहले प्रश्न, बंद इंडस्ट्रीज को खोलने का संबंध है, उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी । दो तरह के फर्टिलाइजर्स प्लान्ट्स है, एक फर्टिलाइजर प्लान्ट गैस के द्वारा चलते है, वे वायबल है। जो नापथा के द्वारा चलते है, वे अनवायबल है इसके कारण से काफी प्लान्ट्स बंद हो गए है । इनमें उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, बिहार का बरौनी, इधर दुर्गापुर है, हल्दिया में तो शुरु ही नहीं हुआ है, हमारे बगल में झारखण्ड में सिंदरी है, आंध्र प्रदेश का भी है। इस तरह से ये प्लान्ट्स बहुत पहले से बंद है। इसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी। जो अभी उपाध्यय जी है, वे हमारे मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में यह बनी थी, वह कमेटी आई है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है, जब तक गैस की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है जहां तक आपका दूसरा प्रश्न प्रश्न है कि क्या जो नए सिस्टम हैं, नई व्यवस्था है, उसमें जो सबसिडी दी जाती है, वह कंपनी को दी जाती है और उसके बदले में किसान को दी जाए। यह देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम भी चाहते है। लेकिन किसान को डायरेक्ट देने का मतलब है कि वह सर्टिफिकेट कहां से लाएगा, कितना दिया जाएगा, फिर बी0डी0ओ0 एस0डी0ओ0 का राज होगा, फिर उन्हें जांचो? इन कारणों से यह व्यावहारिक नहीं है इसलिए जो सब्सिडी कंपनी को दी जाती है उसकी निगरानी सरकार रखती है ।

SHRI K. CHANDRAN PILLAI: Sir, as in the case of availability of MoP, a very serious situation is emerging in the case of phosphatic fertilizers, that is, DAP. There is a shortage. In this situation, what steps are the Ministry going to take to rectify the gap? Since the international prices of phosphoric acid and rock phosphates are going up, there is a big shortage. This is a very serious situation. I want to know from the hon. Minister the steps that the Government is going to take to face the situation.

श्री राम विलास पासवानः सभापति जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दाम काफी बढ़ है, खासकर के एम0ओ0पी0 की कीमत , जो 1999 से लेकर 2003 तक 100 डॉलर से 124 डॉलर प्रति टन थी, इस बार उसका दाम 180 डॉलर पर तय हुआ है। इसके कारण से काफी विलंब भी हुआ, क्योंकि पहले 24 मार्च को डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप 157 डॉलर पर दीजिए, लेकिन उसके बाद से लगातार दाम बढ़ने के कारण हमारे सामने दिक्कत आ गई थी। जब हमने सरकार संभाली तो देखा कि एवरेज कीमत, जो 100 डॉलर से 124,125 डॉलर के बीच तय है, उसमें एकाएक 180 डॉलर की मांग हो रही है, तब मैंने उसे रोक दिया और कहा कि जो पहले की कीमत

है, उस पर देने के लिए उनसे कहिए और सरकार बाद में जो निर्णय लेगी, वह हम दें देंगे। इस मामले को हम कैबिनेट में ले गए, क्योंकि कभी भी अंगुली उठ सकती है कि इतने दाम कैसे बढ़ गए, 650 करोड़ रुपए का अपने एक्ट्रा बोझ क्यों डाल दिया । इस कारण से विलंब हुआ । लेकिन अंत में सरकार ने निर्णय ले लिया कि 180 डालर पर ही देना है। लेकिन इसके कारण से डिमांड और सप्लाई में कोई कठिनाई नहीं आई है। हमारे पास पूरी फिगर है, जिसके मुताबिक हमारे पास प्रारंभिक भंडार 2.76 लाख टन था। सभापति जी, हमारे पास आवश्यकता , 10.48 लाख की थी और 31. 7. 2000 तक हमने 5.40 लाख टन आयात किया व बिक्री 5.3 लाख टन हुई । इस अवधि में बिक्री पिछली बार जरुर कम हुई थी अर्थात् 3.51 लाख की बिक्री हुई थी। मतलब हमारे पास डिमांड 5.36 लाख टन की आई और उस सम्य तक हमारे पास करीब 8 लाख टन की उपलब्धि थी जिसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। महोदय, कुछ राज्यों से शिकायत आई थी और वह यह थी कि उनके पास सामान था, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि शायद टाइम की देरी हो, इसलिए वह पहले से मंगाकर रखना चाहते थे, लेकिन जहां-जहां से शिकायत आई, मैंने पता लगाया। हमने अपने डिपार्टमेंट में सेल खोल रखा है और प्रत्येक दिन मैंने एक ऑफिसर की ड्यूटी लगा रखी है कि वह हर सरकार को टेलीफोन करके पता करता रहे कि उनके पास कमी तो नहीं है। महोदय, हम उसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं है ।

SHRI MATILAL SARKAR: I would like to know from the hon. Minister whether he is aware that fertilizers are not supplied to the North Eastern States, particularly to Tripura on time. Although requisition is made very much on time by the State Governments, very often fertilizer reaches there when the season is over. Will the hon. Minister ensure that fertilizer reaches the farmers on time?

श्री राम विलास पासवान: सर, हमारे पास जहां-जहां से डिमांड आई थी, उसकी हमारे पास लिस्ट है। ये 18 राज्य है- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक , केरल , तमिलनाडु, गुजरात , मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान , हरियाणा, पंजाब , उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल , बिहार झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसाम । इसमें आसाम में उपलब्धता 55 हजार टन की है और उनके पास आवश्यकता केवल 18 हजार टन की है। महोदय, नॉथ ईस्ट की हमारे पास कोई डिमांड नहीं आई है ।

डा0 छत्रपाल सिंह लोढा: सभापति जी, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पशिचमी उत्तर प्रदेश में एम0ओ0पी0 की सप्लाई मांग के अनुसार नहीं हो पाई, इसके क्या कारण थे तथा बिहार सरकार के द्वार एम0ओ0पी0 की सप्लाई का वैरीफिकेशन न होने के कारण वहां किसानों को एम0ओ0पी0 उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इस संबंध में केन्द्र सरकार क्या व्यवस्था करेगी?

श्री राम विलास पासवानः जहां तक एम0ओ0पी0 का सवाल है, एक बात समझ लीजिए कि एम0ओ0पी0 डिकंट्रोल्ड है, एम0ओ0पी0 सरकार सप्लाई नहीं करती है, यह टोटली डिकंट्रोल्ड है, डिकैनलाइज्ड है। वहां से लोग मंगाते है, डिस्ट्रीब्यूट करते है और उसको हम देखते है। उस परिस्थिति में जहां से हमारे पास शिकायत आती है, उसको हम तुरंत उस कंपनी को कहकर कोशिश करते है कि पूरा करने का काम करे।

जहां तक आप ने बिहार के संबंध में कहा, बिहार में दिक्कतें हैं क्योंकि जब कोई कंपनी खाद बेचती है और 80 प्रतिशत कंपनी डिकंट्रोल्ड है तो उसको 80 प्रतिशत ऑडिट सर्टिफिकेट के आधार पर पैसा मिलता है तथा 20 परसेंट पैसा स्टेट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का जो सर्टिफिकेट आता है, उस आधार पर दिया जाता है। महोदय, दुर्भाग्य से बिहार के संबधं में सी0ए0जी0 ने सन् 2000 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि 1994 और 1998 के बीच 162 करोड़ के गलत सर्टिफिकेट दिए गए। उसके बाद कृषि विभाग ने उस सब्सिडी को रोक दिया। उसके रुकने से 1998 के बाद से बिहार में कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया ग्या जिस कारण वहां परेशानी है। सभापति महोदय, कंपनीज का कुल 520 करोड़ रुपया सर्टिफिकेट के अभाव में बकाया है और वह कंपनी उसे भेजने के लिए लाचार है। इसके लिए हमने मुख्य मंत्री के लेवल पर भी बात की है और सेक्रेटरी के लेवल पर चिट्ठी भी लिखी है ।

ज्यों ही वह मामला सार्ट-आउट हो जायेगा, मैं समझता हूं कि यह प्रॉब्लम साल्व हो जायेगी ह।...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः सभाप्ति महोदय, इसके कारण किसान क्यों सफर करे? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः बैठिये, बैठिये। ...(**व्यवधान**)... नेक्स्ट क्वेश्चन । ...(**व्यवधान**)... नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीमती सविता शारदा । ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः यह मामला बहुत पुराना हो चुका है। ...(**व्यवधान**)... किसान सफर कर रहे है। ...(**व्यवधान**)... बिहार में सात वर्ष से ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः श्रीमती सविता शारदा। ...(**व्यवधान**)... श्री मती सविता शारदा...(**व्यवधान**)...

प्रो0 राम देव भंडारीः आपने तो किसानों को देखा नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नैक्स्ट क्वेश्चन।...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।...(**व्यवधान**)... नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती सविता शारदा । ...(**व्यवधान**)... आप कवेश्चन करना चाहती है? श्रीमती सविता शारदा । ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः सर, यह बहुत गंभीर मामला है ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अब आप इसको छोडिये । ...(**व्यवधान**)... ऐसे नहीं होगा। आपका नाम मेरे पास नहीं आया है, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः सर, मंत्री भी बिहार से है, सरकार भी बिहार से है ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये ।...(**व्यवधान**)... आप पहले बैठिये। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर आकर बोलिए ।...(**व्यवधान**)... नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती सविता शारदा । ...(**व्यवधान**)... ठीक है। मैं देख रहा हूं। श्रीमती सविता शारदा ।...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवानः सर, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैंने जैसा कहा कि प्रिवियस गवर्नमेंट ने यदि दाम तय कर दिये होते, तो एमओपी का, पोटाश का आयात उसी समय हो गया होता। हमने 22 मई को कार्यभार ग्रहण किया । उस समय मार्च तक डिपार्टमेंट ने या सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया । जब हमारे पास फाइल आई तो उसका जो मूल्य था वह 124 डालर से बढ़कर 180 डालर हो गया था। उस पर हमारे साइन की आवश्यकता थी और यह हमारे लिए बहुत डिफीकल्ट काम था। मैं अपैइ इमेज पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहता था, इसके कारण विलम्ब हुआ, प्रिवियस गवर्नमेंट की गलती के कारण विलम्ब हुआ ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : श्रीमती सविता शारदा ।...(**व्यवधान**)...

डा0 छत्रपाल सिंह लोढाः प्रीवियस गवर्नमेंट की गलती के कारण नहीं हुआ ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठिएय, छत्रपाल सिंह जी, बैठिये । ...(**व्यवधान**)... बैठिये। आप बोलिये ।

इंटरनेट के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करना

*368. **श्रीमती सविता शारदाः** क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में ठेका प्रथा के कारण हो रहे अपराधों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इंटरनेट के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?